

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे इस चिन्तनक प्रवृत्ति पर अविलम्ब ध्यान दें और इस मामले में प्रभावी कदम उठाएँ ;

(घ) क्या सरकार ने इन अदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों में उपाय, माधन आदि जुट कर सामान्य शैक्षणिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. साहू) : (क) पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की दरों के आंकड़ें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा पाँचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1986) के अन्तर्गत एकत्र नहीं किए गए थे।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) आपरेशन ब्लैकबोर्ड की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1987-88 में आरम्भ की गई थी जिसका उद्देश्य सभी प्राइमरी स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से शैक्षिक सुविधाओं में पर्याप्त सुधार करना था। इस योजना का एक घटक सभी प्राइमरी स्कूलों में पाठ्यचर्या अध्यापकों के लिए पाठ्यपुस्तक/गाइड, नक्शे शैक्षिक चार्ट, योग्यता ग्लाक, खिलौने और खेल उपकरण संगीत उपकरण स्कूल पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएँ प्राइमरी विज्ञान किट, लघु और किट, गणित किट, श्याम पट, चाक तथा शाइन आदि जैसे अनिवार्य शिक्षण अध्यापन उपकरणों का प्रावधान करने है। योजना में यह उल्लेख किया गया है कि खण्डों के चयन में वरीयता उनको दी जानी चाहिए जो शैक्षिक रूप से उपेक्षित हैं और जहाँ पर अनुसूचित जातियों और शैक्षिक रूप से उपेक्षित अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों का बाहुल्य हो।

दिल्ली राजहरा-जगदलपुर रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य

2315. श्रीमती रत्न कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

(क) मध्य प्रदेश में दिल्ली राजहरा-जगदलपुर रेल लाइन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य कब पूरा किया गया ;

(ख) क्या निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह कब तक शुरू कर दिये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबोर प्रसाद) : (क) सर्वेक्षण फरवरी 1988 में पूरा कर लिया गया था।

(ख) जी नहीं। बहुत से वैकल्पिक प्रस्ताव अभी भी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. तथा इस्पात एव खान मन्त्रालय के विचाराधीन हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Expansion of parking bay at Goa Airport

2316. SHRI JOHN F. FERNANDES : Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Dabolim Airport in Goa does not have enough parking bay to accommodate two Air-Buses at a time, inspite of this, airport being used for International flights;

(b) whether it is also a fact that quite often planes are made to wait on the runway for a considerable time when flights arrive late; which has become a common phenomenon with Indian Airlines these days; and

(c) if so, whether Government would consider to expand the parking bay on a

priority basis, since there is ample space for expansion at the said airport?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL):

(a) The parking bay has been designed to accommodate an Airbus and one B-737 and not for two Airbuses at a time.

(b) No, Sir.

(c) The question of expansion of the apron to meet the future requirements is being considered by the NAA. However, land required for expansion is not available with the National Airports Authority and a request has been made to the Indian Navy to transfer additional land required for this purpose.

Rates for advertisement boards at railway stations/platforms

2317. **SHRI N. RAJANGAM:** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have fixed any rates for advertisement boards at

stations/platforms including the New Delhi Station;

(b) if so, what are these rates, along with the sizes;

(c) whether any charges are being recovered from the book-stall contractors at Platform No. 1 for providing neon sign board of Times of India; and

(d) if so, the details of charges recovered during the last three years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MAHABIR PRASAD): (a) Yes, Sir.

(b) A Statement is attached (See below).

(c) The Plastic Sign of Times of India displayed over a bookstall at Platform No. 1 of New Delhi Station is being charged from M/s. Times of India through an advertising agency.

(d) A sum of Rs. 21,800/- has been recovered during the last three years.

Statement

Rates for Advertisement Boards

Sl No.	Area	Rates
1	1 to 100 sq. ft.	Rs. 21/- per sq. ft. per annum
2	101 to 250 sq. ft.	Charges for the first 100 sq. ft. (Rs. 2100/-) plus Rs. 15/- per sq. ft. per annum for the balance.
3	251 to 500 sq. ft.	Charges for the first 250 sq. ft. (Rs. 4350/-) plus Rs. 11/- per sq. ft. per annum for the balance.
4	501 to 750 sq. ft.	Charges for the first 500 sq. ft. (Rs. 7100/-) plus Rs. 9/- per sq. ft. per annum for the balance.
5	751 to 1500 sq. ft.	Charges for the first 750 sq. ft. (Rs. 9350/-) plus Rs. 6/- per sq. ft. per annum for the balance.
6	1501 to 3000 sq. ft.	Charges for the first 1500 sq. ft. (Rs. 13,850/-) plus Rs. 4/- per sq. ft. per annum for the balance.
7	3001 sq. ft. and above	Charges for the first 3000 sq. ft. (Rs. 19,850/-) plus Rs. 3/- per sq. ft. per annum for the balance.